एकजुट होकर चुनौतियों का मुकाबला करो

*** विश्व शांति के लिए संघर्ष करो**

*** बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करो**

*** फूटपरस्त ताकतों को शिकस्त दो**

*** मजदूर किसान गठबंधन का निर्माण करो**

चंडीगढ़ में, 1 से 3 दिसम्बर तक सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 64 वर्किंग कमेटी सदस्यों ने हिस्सा लिया. सीटू अध्यक्ष, बी टी रणदिवे द्वारा संगठन का लाल झंडा फहराये जाने और वर्किंग कमेटी सदस्यों द्वारा शहीद स्तंभ पर फूलमालाएं चढ़ाए जाने के बाद, सीटू की पंजाब राज्य कमेटी के अध्यक्ष, बलवंत सिंह के स्वागत भाषण के साथ बैठक शुरू हुई.

बी टी रणदिवे के अध्यक्षीय भाषण के बाद (जो हम दिसम्बर के सीटू मजदूर में प्रकाशित कर चुके है) बैठक ने नृसिंह चक्रवर्ती, भोला बसु और पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बने शहीदों को तथा गुंडा गिरोहों के हमलों में मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रस्ताव स्वीकार किये. इसके बाद पी. के. गांगुली ने क्रेडेसियल कमेटी तथा प्रस्ताव उपसमिति के सदस्यों के नाम का प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार कर लिया गया.

क्रेडेंसियल कमेटी में पी सत्यनारायण (संयोजक), चित्त व्रत मजुमदार, के पद्मनाभन व रंजीत वसु एवं प्रस्ताव उपसमिति में पी. के गांगुली (संयोजक), सुनील वसुराय, ए के पद्मनाभन एम एम लॉरेंस तथा पी संभगिरि शामिल थे.

इसके बाद, सीटू महासचिव, समर मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बम्बई में हुए छठे सीटू सम्मेलन के बाद की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय क्षेत्र के घटनाविकास का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए, इस संदर्भ में सीटू की गतिविधियों की आत्मालोचनात्मक समीक्षा की गई थी. रिपोर्ट में, संघर्ष, के कछ खास क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है, जिनमें अनवरत संघर्षों का निर्माण करना, सीटू के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य है. ये क्षेत्र है : शांति के लिए संघर्ष, फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ संघर्ष; सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ तथा सार्वजनिक क्षेत्र की हिफाजत के लिए संघर्ष; काम के लिए अधिकार को बुनियादी अधिकार के रूप में स्वीकार किए जाने की मांग को लेकर बेरोजगारों को लामबंद करने के लिए संघर्ष; ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष तथा ट्रेड यूनियनों के महासंघ के गठन की जरूरत और किसानों के साथ मजदूर वर्ग की मैत्री कायम करने के लिए संघर्ष.

शांति के लिए संबर्ष के महत्व को रेखांकित करते हुए, सीटू महासचिव की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल 1 सितंबर को शांति दिवस के पालन को पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा सफलता मिली है, लेकिन इसके साथ ही, भारत में शांति आंदोलन की कमजोरियों को भी रेखांकित किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा संदर्भ में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद का तकाजा है कि शांति के लिए संघर्ष को और तेज किया जाय. समर मुखर्जी ने आगे कहा कि अक्टूबर क्रांति के बाद के सत्तर सालों के इतिहास ने साबित किया है कि 1917 में शांति की आज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद से सोवियत संघ तथा समाजवादी व्यवस्था ने लगातार विश्व शांति की रक्षा की है और युद्ध का लगातार विरोध किया है. सोवियत संघ के नेतृत्व में शांति के लिए जो विश्वव्यापी संघर्ष चल रहा हें, उसीके दबाव के चलते रीगन प्रशासन को मध्यम मार क्षमता की मिसाइलें हटाने पर समझौते के लिए राजी होना पड़ा है.

लेकिन इसके साथ ही, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि अमरीकी साम्राज्यवादी अब भी अपना अंतरिक्ष युद्ध छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और विश्व प्रभुत्व की अपनी साजिशें जारी रखे हुए हैं. वे रंगभेदी तथा नस्लपरस्त निजामों को और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के खिलाफ फासी तानाशाहों को समर्थन देने में लगे हुए हैं. युद्ध के सबाल को, साम्राज्यवाद के चरित्र से जोड़ते हुए, रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि जब तक साम्राज्यवाद मौजूद है, युद्ध का खतरा बना ही रहेगा. इसलिए शांति के लिए संघर्ष को कुछ खास दिनों के पालन तक सीमित न रखकर, अनवरत रूप से शांति के लिए संघर्ष के निर्माण की जरूरत है, इसके साथ ही, मजदूरों को निरस्त्रीकरण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच के अविभाज्य रिश्ते के बारे में भी शिक्षित करना जरूरी है.

फूटपरस्त ताकतों की बढ़ती गतिविधियों पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए रिपोर्ट में सीटू राज्य कमेटियों तथा यूनियनों का आह्वान किया गया है कि देश की एकता व अखंडता की रक्षा के लिए मजदूर वर्ग तथा आम जनता को लामबंद करने के लिए अनथक प्रयास करें. इस सिलसिले में समर मुखर्जी ने पृथकतावादी ताकतों के खिलाफ पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा असम में सीटू के बहादुरीपूर्ण संघर्ष की सराहना की. उन्होंने कहा कि अनेक दूसरी ट्रेड यूनियनों में इस संघर्ष के प्रति पर्याप्त जागरूकता दिखाई नही देती है और इससे सीटू की यह

जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि साम्राज्यवादी ताकतों की साजिश को बेनकाब करे, जो हमारे देश की एकता तथा अखंडता को कमजोर करने के लिए इन फूटपरस्त तथा सांप्रदायिक ताकतों को हर तरह का बढ़ावा तथा मदद दे रही है. इस संदर्भ में उन्होंने देश की शासक पार्टी, कांग्रेस (आइ) की नीति की भी आलोचना की, जो क्षुद्र चुनावी लाभों के लिए इन ताकतों के साथ हाथ मिलाती है तथा सिद्धांतहीन समझौते करती है और इस तरह देश की एकता तथा अखंडता को कमजोर ही कर रही है. उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में सांप्रदायिक ताकतों की बढ़ती हरकतों की ओर ध्यान खींचते हुए समर मुखर्जी ने राज्य कमेटियों का आह्वान किया कि इस स्थिति में कारगर ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए एकजुट आंदोलन के निर्माण के अपने प्रयासों को और तेज करें. इसी संदर्भ में केरल तथा प. बंगाल की जीतों का अभिनंदन करते हुए रिपोर्ट में इस पर जोर दिया गया कि सभी राज्यों में सांप्रदायिकता तथा पृथकतावाद की ताकतों के खिलाफ एक अनवरत संघर्ष चलाया जाय और देश की एकता तथा अखंडता की हिफाजत करने तथा सामराजी साजिशों को शिकस्त देने के लिए, तमाम धर्मनिरपेक्ष तथा देश भक्त ताकतों को एकजुट करने के लिए संघर्ष तेज किया जाय.

बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष की जरूरत पर जोर देते हुए रिपोर्ट में प. बंगाल, केरल तथा असम राज्य कमेटियों को बधाई दी गयी, जिन्होंने इस सिलसिले में जबर्दस्त कार्यक्रम आयोजित किए हैं. रिपोर्ट में इस तथ्य पर गौर किया गया कि अनेक राज्य कमेटियों ने, मिलबंदियों तथा उद्योगों के बीमार होने के खिलाफ, जिनसे बेकारी बढ़ती है, अनेक कार्यक्रम चलाए हैं, फिर भी, रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि बेकारी की समस्या को, मिलबंदियों तथा छंटनी आदि के जरिए पैदा होने वाली अतिरिक्त बेकारी तक ही सीमित करके नहीं देखना चाहिए. इसके बजाय, बेकारी के खिलाफ लड़ाई को इस प्रकार चलाया जाना चाहिए कि ऐसे सारे लोग भी इस लड़ाई का हिस्सा बन सकें, जिन्हें पूंजीवादी विकास की देश की सरकार की नीतियों के चलते कभी रोजगार का मुंह देखने का ही मौका नहीं मिला है, और उन्हें भी इस लड़ाई में खींचा जा सके. समर मुखर्जी ने कहा कि सीटू को इस तबके की ओर से सीधे-सीधे मांगे उठानी चाहिए और इस मांग के लिए आंदोलन करना चाहिए कि काम के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाय और बेकारों को जब तक रोजगार नहीं मिलता है, राहत दी जाय.

इसी क्रम में समर मुखर्जी ने सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की, जिनके चलते कीमतें लगातार बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है और औद्योगिक बीमारी तथा कारखाना बंदियां बढ़ रही हैं. चालीस साल के पूंजीवादी नियोजन ने किसानों, मजदूरों तथा दूसरे मेहनतकशों को तो पहले ही तबाह करके रख दिया है और अब सरकार, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मांगों के आगे ज्यादा से ज्यादा घुटने टेकते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र को नष्ट करने में लगी हुई है और निजीकरण की मुहिम चला रही है. एक ओर तो उसने मजदूर वर्ग को, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा इजारेदारियों के शोषण के सामने अरक्षित छोड़ दिया है और दूसरी ओर देश की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति तथा संप्रभुता को ही खतरे में डाल दिया है. इस सिलसिले में रिपोर्ट में, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों तथा अफसरान को उनके संघर्ष के लिए बधाई दी गई है और सीटू राज्य कमेटियों तथा यूनियनों का आह्वान किया गया है कि सरकार की प्रतिगामी नीतियों के खिलाफ अपना संघर्ष तेज करें और एक राजनीतिक काम के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र की हिफाजत के काम को अपने हाथ में लें.

समर मुखर्जी ने असंगठित मजदूरों को संगठित करने के सवाल, नये औद्योगिक संबन्ध विधेयक, नये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, न्यूनतम मजदूरी के सवाल पर देशव्यापी संघर्ष, कामगार महिलाओं की समस्याओं तथा राज्यों में उनकी समन्वय समितियां गठित करने की जरूरत आदि अनेक मुद्दों को भी उठाया. उन्होंने, सितम्बर के देशव्यापी किसान आंदोलन का अभिनन्दन किया और इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग करने और सुखा तथा बाढ़ राहत के लिए किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए, राज्य कमेटियों को बधाई दी.

देश में ट्रेड यूनियन आंदोलन की मौजूदा स्थिति की विस्तार से चर्चा करते हुए सीटू महासचिव ने, ट्रेड यूनियन एकता की जरूरत को रेखांकित किया. इस सिलसिले में अनवरत संघर्ष करने के लिए उन्होंने सीटू राज्य कमेटियों को बधाई भी दी. सीटू के छठे सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण की उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा: "भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के सामने असल समस्या यह है कि कैसे उन अलग-अलग ट्रेड यूनियन केन्द्रों तथा फेडरेशनों को एकजुट किया जाय, जिनकी पृष्ठभूमि तथा राजनीतिक दृष्टिकोण में भारी अंतर है और ट्रेड यूनियन आंदोलन के सिलसिले में जिनकी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों में अंतर हैं." इसी क्रम में सीटू महासचिव ने, ट्रेड यूनियनों तथा फेडरेशनों के एक ऐसे महासंघ के निर्माण के सीटू के आह्वान को दुहराया, जिसमें सर्वसम्मति से फैसले लिए जायें और श्रम तथा आर्थिक नीति सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर खुलकर विचार-विमर्श हो सके.

अंत में समर मुखर्जी ने, वामपंथी पार्टियों की पहल पर, उनसे जुड़े जनसंगठनों द्वारा 9 दिसम्बर के दिल्ली मार्च के आह्वान के महत्व को रेखांकित किया और सीटू यूनियनों का आह्वान किया कि वामपंथी, जनतंत्रित तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने का अपना आंदोलन तेज करें. यही ताकतें हैं, जो तानाशाह कांग्रेस (आइ) को सत्ता से हटा सकती हैं और इसके साथ ही सांप्रदायिक तथा दूसरी फूटपरस्त ताकतों को

अलग-थलग डाल सकती हैं तथा वास्तविक विकल्प पेश कर सकती हैं.

महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस में हिस्सा लेते हुए विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने राज्यों में मुख्य मुद्दों पर चलाये गये संघर्षों की आत्मालोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की, ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष का अपना अनुभव रखा और अब तक सामने आयी खामियों को दूर करने, सीटू की स्वतंत्र गतिविधियों को तेज करने और मजदूर वर्ग के लिए महत्व रखनेवाले सभी मुद्दों पर सक्रिय तथा कारगर ढंग से हस्तक्षेप करने का निश्चय प्रकट किया. बहस में, वर्किंग कमेटी के बीससदस्यों ने हिस्सा लिया. केरल से के एन रवीन्द्रनाथ, भी. बी. चेरियन, एम एम लॉरेन्स; प. बंगाल से सुनिल बसुराय, आनन्द पाठक व सुभाष बोस, तामिलनाडु से आर उमानाथ ए. के. पद्मनामन; मंगतराम पासला (पंजाब), एस एन सोलंकि (हरियाणा), पी. सत्य-नारायण, बालाजी दास (आंध्र प्रदेश), एस. बी. भारद्वाज (दिल्ली), पी संभ्गिरि (महाराष्ट्र), चन्डी प्रसाद (बिहार), अमल घोषदस्तिदार (असाम) अजेय राउत (उड़िसा), हर सहाय सिंह (उत्तर प्रदेश), एस कुमार (मध्य प्रदेश) तथा पी. के. गांगुली (केन्द्र) ने बहस में हिस्सा लिया. समर मुखर्जी ने बहस में उठे मुद्दों का जवाब दिया, जिसकेबाद सर्वसम्मति से रिपोर्ट स्वीकृत हुई.

अन्य रिपोर्ट और प्रस्ताव

एम के पंधे ने सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि किस प्रकार सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में अनेक कदम उठाये हैं. उन्होंने 21-22 नवम्बर को हैदराबाद में हुई सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियन वर्कशाप की रिपोर्ट दी जिसमें हर स्तर पर, महंगाई के पूर्ण निष्प्रभावीकरण की मांग उठाई गई है. इस वर्कशाप ने केन्द्र सरकार की इसके लिए आलोचना की कि उसने प. बंगाल के इंजीनियरिंग तथा अन्य उद्योगों को अंतरिम राहत के दायरे से बाहर रखा है, और प. बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए पूर्ण समर्थन का आह्वान किया.

ए के पद्मनामन ने तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग पर रिपोर्ट पेश की और देश में कपड़ा उद्योग की गम्भीर स्थिति तथा राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलायी जा रही कई कपड़ा मिलें बन्द कराने की सरकार की कोशिशों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, कपड़ा उद्योग के सिलसिले में एक देशव्यापी संघर्ष चलाने की जरूरत पर जोर दिया. प. बंगाल में कपड़ा उद्योग की स्थिति के संबंध में जैमिनी साहा ने भी ऐसी ही रिपोर्ट भेजी थी, जो वर्किंग कमेटी के सामने रखी गयी.

पी के गांगुली ने चीनी उद्योग के मजदूरों के आंदोलन तथा 12 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल के चीनी मजदूरों के फैसले के बारे में रिपोर्ट दी. उन्होंने बताया कि चीनी मजदूरों से संबंधित सीटू समन्वय समिति इस पक्ष में है कि चीनी उद्योग की सीटू यूनियनों की एक फेडरेशन का गठन किया जाय.

जगदीश दास ने जूट उद्योग के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की और जूट उद्योग के राष्ट्रीकरण के लिए जूट मजदूरों द्वारा चलाये जा रहे संयुक्त आंदोलन पर प्रकाश डाला.

ई बालानंदन ने भारतीय विद्युत कामगार फेडरेशन (ई ई एफ आइ) के सम्मेलन, बिजली उद्योग में सीटू तथा एटक के संयुक्त आंदोलन और 8 दिसम्बर के दिल्ली के प्रस्तावित संयुक्त पदर्शन की रिपोर्ट रखीं.

विमल रणदिवे ने कामगार महिलाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश की. उन्होंने, सीटू की कामगार महिला समन्वय समिति की बैठक तथा अपनी मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों में कामगार महिलाओं द्वारा चलाये जा रहे संघर्षों के बारे में बताया और जल्द से जल्द राज्य स्तर पर कामगार महिला समन्वय समितियां गठित किये जाने की जरूरत पर जोर दिया.

वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर क्रांति की सत्तरवीं सालगिरह, बंगला देश की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति, 9 दिसम्बर का दिल्ली मार्च, पंजाब में स्थिति, त्रिपुरा चुनाव, औद्योगिक संबंध विधेयक, नयी उपभोक्ता सूचकांक श्रृंखला, आइ टी सी (बंगलोर) की हड़ताल, पंजाब में जुनियर इन्जीनियरों की हड़ताल, उड़ीसा सीमेंट्स में तालाबंदी और बारिपदा कताई मिल में हड़ताल पर प्रस्ताव स्वीकार किये.

का. बी. टी. आर का समाहार भाषण

वर्किंग कमेटी की तीन दिन का बैठक की बहस का समाहार करते हुए, बी टी आर ने सबसे पहले तो बैठक के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए पंजाब राज्य कमेटी को वधाई दी जिसने आतंकवादियों की सारी धमकियों के बीच बड़ी सफलता के साथ बैठक का आयोजन किया. बी टी आर ने कहा कि इस बैठक और इससे पहले चलाये गये राज्यव्यापी अभियान तथा बैठक के समापन के मौके पर आयोजित विशाल रैली का, पंजाब के मेहनतकशों पर जबर्दस्त असर पड़ेगा और वे, फूटपरस्त ताकतों की चुनौती का और मजबूती से सामना करेगे. बी टी आर. ने दार्जिलिंग, त्रिपुरा तथा असम के मजदूरों को भी बधाई दी, जो बड़ी बहादुरी के साथ फूटपरस्त ताकतों के साथ रहे हैं. उन्होंने तमिलनाडु राज्य कमेटी को भी बधाई दी, जो सफलता के साथ राज्य में तमिल कट्टरतावादी तत्वों का मुकावला कर रही है.

तीन दिन की बैठक में, वक्ताओं के हस्तक्षेप की भी बी टी आर ने सराहना की और कहा कि कई वर्किंग कमेटी सदस्यों ने पहले से तैयार, निश्चित टिप्पणियां दी हैं, जो ठीक मुद्दे पर तथा सुलझे हुए ढंग से बहस की जरूरत के प्रति बढ़ती जाग-रूकता को ही दिखाता है.

(शेष पृष्ठ 22 पर)

को शामिल करने के लिए सभी यूनियनों को दबाव डालना चाहिए.

वर्कशॉप ने, 18 दिसम्बर 1987 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 'भूखहड़ताल' करने का फैसला लिया है. इस दिन सिलसिलेवाररूप से हर शिफ्ट से मजदूर हिस्सा लेंगे और कैन्टीन सुविधाओं का भी बहिष्कार करेंगे. तथा अपना विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री को तार भेजेंगे और इसकी प्रतिआं उद्योग के प्रमुख तथा सम्बद्ध मंत्रालय को भी भेजेंगे.

वर्कशॉप ने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का आह्वान किया कि वह हड़ताल सहित अन्य कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के वेतन नीति बदलने के लिए केन्द्र सरकार को मजबूर किया जा सके.

राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर

हजारों मजदूर संसद पर गिरफ्तारियां देंगे

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने देश भर के मजदूर वर्ग का आह्वान किया है कि उद्योगों में बढ़ती मिलबंदी तथा रुग्णता, महंगाई, मूल्य सूचकांक में हेरा-फेरी तथा प्रस्तावित मजदूर वर्गविरोधी औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के खिलाफ 18 अप्रैल को अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाये. इस रोज देश भर में विरोध प्रदर्शनों तथा रैलियों का आयोजन किया जायगा. इस रोज दिल्ली में, केंद्र सरकार की मनमानी नीतियों पर विरोध प्रकट करते हुए हजारों मजदूर संसद पर गिरफ्तारी देंगे. यह फैसला, 21 दिसम्बर को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक में लिया गया. आइ टी यू सी (दारा) के जे एस दारा ने बैठक की अध्यक्षता की, एच एम एस के उमरामल पुरोहित, वी त्यागी तथा एस पी सिंह; सीटू के एम के पंधे, पी के गांगुली तथा एस भारद्वाज एटक के होमी दाजी तथा टी एन सिद्धांत; बी एम एस के ओ पी आधी तथा आर के भक्त; यू टी यू सी (लेनिन सरणी) के प्रितीश चदा तथा आर के शर्मा; यू टी यू सी के प्रतुल चौधरी तथा टी यू सी सी के डी डी शास्त्री ने बैठक में हिस्सा लिया.

राष्ट्रीय अभियान समिति ने पश्चिम बंगाल के सार्बजनिक क्षेत्र के मजदूरों को उनकी 14 दिसंबर से जारी अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर बधाई दी और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उनकी अंतरिम राहत की मांग स्वीकार करें, जैसा कि उसने केंद्रीय ट्रेड यूनियन को वचन दिया था. राष्ट्रीय अभियान समिति ने देश भर की ट्रेड यूनियनों का आह्वान किया है कि हड़ताली मजदूरों के समर्थन में एकजुटता कार्रवाइयों का आयोजन करें.

राष्ट्रीय अभियान समिति की बैठक ने शुरू में ही सीटू के पूर्व महासचिव तथा राष्ट्रीय अभियान समिति के संस्थापकों में एक का. पी राममूर्ति के आकस्मिक निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त किया. बैठक ने नोट किया कि का. पी आर ने भारत में मजदूर वर्ग के संयुक्त आंदोलन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, राष्ट्रीय अभियान समिति ने मजदूर वर्ग की एकता को मजबूत करने के काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसके लिए कामरेड राममूर्ति आजीवन संघर्ष करते रहे थे.

(पृष्ठ 11 का शेष)

बी टी आर ने, न्यूनतम मजदूरी के लिए हड़ताल, असगठित मजदूरों की रैली तथा बेरोजगारीविरोधी रैली के लिए सफलता-पूर्वक मजदूरों को लामबंद करने के लिए क्रमशः दिल्ली, प. बंगाल तथा असम राज्य कमेटियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि इन कार्रवाईयों की जबर्दस्त सफलता यही दिखाती है कि सीटू की सही लाइन तथा उसके द्वारा मेहनतकशों से जुड़े सही मुद्दे उठाये जाने के फलस्वरूप, ये तबके सीटू की ओर झुक रहे हैं. बी टी आर ने, इन्हीं क्षेत्रों में तथा कामगार महिलाओं के क्षेत्र में भी — जिस क्षेत्र में प. बंगाल कमेटी पिछड़ रही है — सक्रिय प्रयासों के लिए केरल राज्य कमेटी की भी सराहना की. इसके साथ ही उन्होंने, ट्रेड यूनियनों में अल्पसंख्यकों तथा कमजोर तबकों के बीच भी सीटू के काम पर जोर दिया और कहा कि इससे सीटू की स्थिति मजबूत होगी.

शांति के लिए संघर्ष के महत्व को रेखांकित करते हुए बी टी आर ने कहा कि पहली सितम्बर की कार्रवाई को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए, जितना महत्व मई दिवस का है. ये दोनों ही, अंतरांष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के लिए ऐतिहासिक महत्व की तिथियां हैं. ट्रेड यूनियन एकता के लिए संघर्ष का जिक्र करते हुए बी टी आर ने ट्रेड यूनियनों के महासंघ के सीटू के आह्वान को दुहराया. अंत में, 9 दिसम्बर के दिल्ली मार्च का जिक्र करते हुए बी टी आर ने इस मार्च में बड़ी से बड़ी संख्या में शरीक होने का आह्वान किया और एक वामपंथी तथा जनतत्रिक विकल्प के निर्माण की प्राक्रिया के लिए इसे महत्व-पूर्ण बताया. बी टी आर ने, इस कार्यक्रम के लिए सीटू की ओर से एक लाख रुपये के अंशदान की भी घोषणा की.

बैठक के अंतिम चरण में, ज्योति बसु भी उपस्थित थे और उन्होंने सदस्यों का अभिनंदन किया.

आम सभा

3 दिसम्बर की दोपहर में, परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली के आयोजन के साथ सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक का समापन हुआ. पंजाब के कोने-कोने से तथा हरियाणा व हिमाचल जैसी पड़ोसी राज्यों से भी, कम से कम तीस हजार मजदूर, किसान, महिलाएं तथा कर्मचारी इस रैली के लिए चंडीचढ़ पहुंचे. सुबह से ही, लाल झंडे उठाये छोटे बड़े अनगिनत जत्थे चंडीगढ़ में परेड ग्राउंड की ओर बढ़ते दिखायी देने लगे थे. सीटू राज्य अध्यक्ष, बलवंत सिंह ने रैली की अध्यक्षता की और ज्योति बसु, बी टी रणदिवे, हरकिशन सिंह सुरजीत, समर मुखर्जी तथा मंगतराम पासला ने जनसभा को संबोधित किया.